भारतीय वैश्विक परिषद

समाचार पत्रक

अंक : 32 | जनवरी - मार्च, 2023

जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा ने 20 मार्च 2023 को नई दिल्ली में "हिंद-प्रशांत का भविष्य- 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' के लिए जापान की नई योजना-एक अपरिहार्य भागीदार के रूप में भारत के साथ मिलकर" विषय पर 41वां सप्रू हाउस व्याख्यान दिया। इस अवसर पर माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भी उपस्थित थे।

भारतीय वैश्विक परिषद ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत की एससीओ की अध्यक्षता में 23-24 मार्च 2023 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन: पुनःसंयोजन ~ पुनर्जीवन्तता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। विदेश मंत्रालय के सचिव (ईआर) श्री दम्मू रवि ने मुख्य भाषण दिया।

भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा 30 जनवरी 2023 को "संयुक्त राष्ट्र में एकजुटता, संपोषणीयता और विज्ञान के माध्यम से समाधान" पर 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष महामहिम श्री कसाबा कोरोसी द्वारा 40वां सप्रू हाउस व्याख्यान आयोजित किया गया था।

विषय-सूची

झेंगिक्सन जे., दक्षिण एशिया-पश्चिम चीन सहयोग और विकास अध्ययन केंद्र में निदेशक सहायक, दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान, सिचुआन विश्वविद्यालय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द्वितीय एससीओ निवासी शोधकर्ता, 01 जनवरी 2023 4

प्रवासी भारतीय दिवस 2023-अमृत काल के युग में प्रवासी भारतीयों का समारोह" पर पैनल चर्चा, 04 जनवरी 2023 4

श्री अटेम गारंग डेंग डेकुक, सदस्य, संक्रमणकालीन राष्ट्रीय विधान सभा, दक्षिण सूडान ने राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक, भारतीय वैश्विक परिषद से भेंट की, 11 जनवरी 2023 7

राजदूत विजय ठाकुर सिंह, अध्यक्ष, टास्क फोर्स 7- टी 20, भारत, और महानिदेशक, भारतीय वैश्विक परिषद ने थिंक 20 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस में स्पॉटलाइट संबोधन दिया। 13 जनवरी 2023 7

भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र की भागीदारी के अवसर पर, भारतीय वैश्विक परिषद पैनल चर्चा "बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत-मिस्र संबंध" पर चर्चा, 16 जनवरी 2023 7

"भारतीय विदेश नीति के 75 वर्षों का समारोह" पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 17-18 जनवरी 2023 9

इंडोनेशिया के राष्ट्रीय विकास योजना मंत्रालय के राजनीतिक, कानूनी, रक्षा और सुरक्षा मामलों के उप मंत्री स्लैमेट सोएडारसोनो ने भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक, राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की, 18 जनवरी 2023 11

"भारत-बांग्लादेश संबंधों पर विचार" पर गोलमेज चर्चा, 19 जनवरी 2023 12

"संयुक्त राष्ट्र में एकजुटता, संपोषणीयता और विज्ञान के माध्यम से समाधान" पर 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष महामहिम श्री कसाबा कोरोसी द्वारा 40वां सप्रू हाउस व्याख्यान, 30 जनवरी 2023 12

कारागुलोव बातिर-मुखम्मद अज़मातोविच, अग्रणी विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, किर्गिज गणराज्य, भारत के तृतीय एससीओ निवासी शोधकर्ता, 01 फरवरी 2023 14

भारतीय वैश्विक परिषद-आरआईएसी वार्ता "भारत-रूस सामरिक साझेदारी: बदलती विश्व व्यवस्था में नई चुनौतियां और अवसर", 02 फरवरी 2023 15

स्लोवाक गणराज्य के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के राजनीतिक मामलों के महानिदेशक श्री माइकल पावुक के साथ गोलमेज चर्चा, 09 फरवरी 2023 16

टिम हॉल, प्रथम सचिव (नीति), ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग, भारत ने भारतीय वैश्विक परिषद का दौरा किया, 10 फरवरी 2023 17

तिलक देवशेर द्वारा "पश्तून: एक विवादित इतिहास" पर पुस्तक चर्चा, 13 फरवरी 2023 17

भारत में सऊदी अरब साम्राज्य के महामहिम सालेह ईद अल हुसैनी ने को भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक, राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की, 16 फरवरी 2023 18

भारत में ग्वाटेमाला गणराज्य के राजदूत श्री उमर कास्टानेडा सोलारेस ने भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की, 17 फरवरी 2023 19

सीईएसआईसीएएम के निदेशक और कोलम्बिया के वाणिज्य मंत्री के सलाहकार डॉ. सोरया कारो वर्गास ने राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक से भेंट की, 20 जनवरी 2023 19

लातविया गणराज्य के विदेश मंत्रालय की उप विदेश मंत्री सुश्री रीरे के साथ गोलमेज चर्चा, 01 मार्च 2023 20

उजबेकिस्तान के विदेश मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए सूचना और विश्लेषणात्मक केंद्र (सीआईआरएस) के निदेशक राजदूत डोनियोर कुरबानोव ने भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की, 03 मार्च 2023 20

श्री डेमन विल्सन, अध्यक्ष और सीईओ, एनईडी, वाशिंगटन ने भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक, राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की, 06 मार्च 2023 21

श्री पैट्रिक कुगिल, वरिष्ठ विश्लेषक, द पोलिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (PISM), पोलैंड ने भारतीय वैश्विक परिषद का दौरा किया, 06 मार्च 2023 21

प्रोफेसर चिसाको मासुओ, क्यूशू विश्वविद्यालय, जापान ने भारतीय वैश्विक परिषद का दौरा किया, 14 मार्च 2023 21

श्री अराई मासायोशी, महानिदेशक, मंत्री सचिवालय, अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जापान ने भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की, 14 मार्च 2023 22

डॉ. अलेक्सी ज़खारोव, अध्येता, हायर स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स (एचएसई), मास्को ने भारतीय वैश्विक परिषद रिसर्च फैकल्टी के साथ वार्ता की, 15 मार्च 2023 22

जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री फुमियो किशिदा द्वारा 41वां सप्रू हाउस व्याख्यान, 20 मार्च 2023 22

भारतीय वैश्विक परिषद-विदेश मंत्रालय एससीओ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: पुनःसंयोजन ~ पुनर्जीवन्तता, 23-24 मार्च 2023 24

भारतीय वैश्विक परिषद ने बेलारूसी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक रिसर्च के साथ "अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग" पर एक समझौता-ज्ञापन किया, 23 मार्च 2023 26

प्रोफेसर डी. सुबाचंद्रन ने एनआईएएस के अनुसंधान शोधकर्ता के साथ भारतीय वैश्विक परिषद शोध-संकाय के साथ वार्ता की, 27 मार्च 2023 27

आउटरीच कार्यक्रम 27

प्रकाशन 29

इंडिया क्वार्टरली - संपादकीय 33

ज़्हेंगिग्ङ जे., दक्षिण एशिया-पश्चिम चीन सहयोग और विकास अध्ययन केंद्र में निदेशक सहायक, दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान, सिचुआन विश्वविद्यालय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरा एससीओ निवासी शोधकर्ता, 01 जनवरी 2023

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) (2022-2023) की भारत की अध्यक्षता के वर्ष में, भारतीय वैश्विक परिषद दिसंबर 2022 से जून 2023 तक विदेश मंत्रालय के सहयोग से एससीओ निवासी शोधकर्ता कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। सात महीनों में, प्रत्येक एससीओ सदस्य देश से एक नामांकित युवा शोधकर्ता (रूसी वर्णमाला क्रम के एससीओ अभ्यास का पालन करते हुए: कजाकिस्तान-दिसंबर 2022, चीन-जनवरी 2023, किर्गिस्तान-फरवरी 2023, पाकिस्तान-मार्च 2023, रूस-अप्रैल 2023, ताजिकिस्तान-मई 2023 और उजबेकिस्तान-जून 2023) एक महीने की अवधि के लिए भारतीय वैश्विक परिषद के साथ रहेंगे। कार्यक्रम में एससीओ विद्वान की बेंगलुरु, चेन्नई और पांडिचेरी की यात्रा का एक सप्ताह का मॉड्यूल शामिल है, जिसे भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा अपने समझौता-ज्ञापन साझेदार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस), बैंगलोर के सहयोग से समन्वित किया जा रहा है। जनवरी 2023 के महीने में, भारतीय वैश्विक परिषद ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से एक एससीओ विद्वान की मेजबानी की: झेंगिक्सन जेड, दक्षिण एशिया-पश्चिम चीन सहयोग और विकास अध्ययन केंद्र में निदेशक सहायक, दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान, सिचुआन विश्वविद्यालय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उन्होंने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत सहित भारत के प्रमुख थिंक टैंक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ वार्ता की; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली।

प्रवासी भारतीय दिवस 2023-अमृत काल के युग में प्रवासी भारतीयों का समारोह" पर पैनल चर्चा, 04 जनवरी 2023

भारतीय वैश्विक परिषद ने "प्रवासी भारतीय दिवस 2023-अमृत काल के युग में डायस्पोरा का समारोह" पर एक पैनल चर्चा की मेजबानी की। विदेश मंत्रालय में सचिव (सीपीवी और प्रवासी भारतीय मामले) डॉ. औसाफ सईद ने विशेष टिप्पणी की और चर्चा की अध्यक्षता की। भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया। अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष राजदूत वीरेंद्र गुप्ता; - राजदूत अनिल त्रिगुणायत, जॉर्डन, लीबिया और माल्टा में भारत के पूर्व राजदूत; बिनोद खडरिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; और श्री सुशील पंडित, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय मूल के चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पैनलिस्ट थे।

भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने प्रवासी भारतीयों के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रवासी भारतीय दिवस की ऐतिहासिक प्रासंगिकता के बारे में उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले महानतम प्रवासी महात्मा गांधी की 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े प्रवासियों में से एक हैं, जिनकी अनुमानित संख्या दुनिया भर में फैली हुई 32 मिलियन है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने के भारत के दृष्टिकोण को चार सी-केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट और कंट्रीब्यूट-द्वारा चित्रित किया गया है-एक व्यापक ढांचा जो हमारे प्रवासी भारतीयों की देखभाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की विशेष प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए अपनी टिप्पणी समाप्त की, जिसमें यह भारत के जी 20 और एससीओ की अध्यक्षता के साथ मेल खाता है और प्रवासी सदस्यों को उस आत्मविश्वास और ऊर्जा को देखने का अवसर देता है जिसके साथ भारत इन दो महत्वपूर्ण संगठनों के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।

विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) डॉ. औसाफ सईद ने विशेष संबोधन देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रवासी भारतीय विकास मंत्रालय दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संबंधों को जोड़ने और मजबूत करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय, प्रवासी देशों में अच्छी तरह से फैले हुए हैं और एक बहुत ही गतिशील और शक्तिशाली इकाई के रूप में उभरे हैं, जिन्हें उनके कौशल, कड़ी मेहनत और कानून का पालन करने वाली प्रकृति के लिए विश्व स्तर पर पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रवासी दुनिया भर में राजनीतिक प्रभाव भी हासिल कर रहे हैं। यह विश्व मामलों में भारत की बढ़ती प्रमुखता के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। भारत की वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रेषण आदि जैसे कई तरीकों से महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत, लगभग 87 बिलियन अमरीकी डॉलर के साथ, महामारी के चरम के दौरान भी प्रेषण का सबसे अधिक प्राप्तकर्ता था। अकेले मजदूर वर्ग ने कुल प्रेषण में लगभग 54.42 बिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दिया, जो न केवल मौद्रिक प्रवाह बल्कि भारतीय मूल के लोगों के लचीलेपन का भी संकेत देता है। डॉ. सईद ने कहा कि भारत की विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में, प्रवासी भारतीयों को एक जीवित पुल के रूप में माना जाता है, जो भारत और उन देशों के बीच अपने बंधन को मजबूत करता है जहां वे रह रहे हैं। यह बढ़ती प्रमुखता भारत के उच्च-स्तरीय अधिकारियों की सभी महत्वपूर्ण यात्राओं में भी स्पष्ट है, जिसमें मंत्रियों की किसी भी देश की यात्रा शामिल है, जिसमें वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सदैव प्रवासी जुड़ाव हो। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रवासी भारतीय दिवस न केवल प्रवासी भारतीयों के साथ हमारे संबंधों का उत्सव है, बल्कि हमारे प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़े रहने की हमारी इच्छा की अभिव्यक्ति भी है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष राजदूत वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रवासी भारतीयों में अपनी सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति को लेकर मुखरता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की स्थापना प्रवासी जुड़ाव के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा शुरू

की गई एक महत्वपूर्ण पहल रही है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कई तरीकों से योगदान दिया है, जैसे कि निवेश, श्री अटेम गारंग डेंग देंग डेकुक, सदस्य, संक्रमणकालीन राष्ट्रीय विधान सभा, दक्षिण सूडान, ने 11 जनवरी 2023 को भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की और दक्षिण सूडान में थिंक टैंक के साथ संभावित संस्थागत संबंध और अनुसंधान सहयोग पर चर्चा की। वह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के तहत भारत में थे और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; हालांकि, अधिक संभावनाएं हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों में भारतीय सीईओ भारत में सुविधाएं स्थापित करने में अपने संगठनों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। राजदूत गुप्ता ने कुछ पहलों का सुझाव दिया जो वित्तीय सहायता के माध्यम से पीआईओ संस्थानों को सहायता प्रदान करने जैसी की जा सकती हैं। प्रवासी युवाओं के साथ जुड़ाव को आगे बढ़ाने पर, पीआईओ छात्रों को अधिक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकती हैं। भारत को जानो कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए अधिक पहुंच की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

जॉर्डन, लीबिया और माल्टा में भारत के पूर्व राजदूत, राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने टिप्पणी की कि आज प्रवासी एक सामरिक संपत्ति बन गए हैं और 4 सी का दृष्टिकोण उन्हें बांधने के लिए एक मैट्रिक्स है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने इस वर्ष भारत को 100 अरब डॉलर के साथ प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता घोषित किया है, जो भारत में प्रवासी भारतीयों के विश्वास का संकेत है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीयों से आता है। अंबासादेर त्रिगुणायत ने आगे कहा कि लोगों के लिए विदेशी रोजगार को प्रोत्साहित करने और सक्षम करने में अधिक सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इस संबंध में, पीआईओ संस्थान और मिशन देशों में रोजगार के अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों की संख्या उसके प्रभाव के बढ़ी है। इस क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ना एक वास्तविक पुल हो सकता है क्योंकि हम अगली शताब्दी में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें एशियाई और अफ्रीकी देशों का वर्चस्व होने जा रहा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बिनोद खडरिया ने सुझाव दिया कि भारतीय प्रवासियों के योगदान असंख्य हैं, जिनका न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है, फिर भी भारतीय प्रवासियों को उनकी क्षमता का उपयोग करने से परे देखने की आवश्यकता है। खडरिया ने संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में प्रवासन को शामिल करने के प्रयासों में शामिल कई जटिलताओं को आगे समझाया। उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक स्तर पर प्रवासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने में वैश्विक दक्षिण का नेता बनने की क्षमता है। उनकी राय में, प्रवासी भारतीय दिवस इस बात पर विचार करने का सही समय है कि क्या भारत जी 20 की अध्यक्षता के माध्यम से या स्वतंत्र रूप से दुनिया के प्रवासी भारतीयों का मूल देश होने का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने यह भी साझा किया कि भारतीय प्रवासियों को अब देश के विकास के लिए एक संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि तीसरी दुनिया के देशों के विकास के लिए एक संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए।

पीआईओ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यकारी अध्यक्ष सुशील पंडित ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की अप्रयुक्त क्षमता का एहसास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में नीतियां अब तकनीकी रूप से सक्षम और पारदर्शी हैं, इस प्रकार पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं और इन क्षेत्रों में पीआईओ की अधिक भागीदारी के लिए एक अवसर का प्रतिनिधित्व करती हैं। सरल नौकरशाही चैनलों को सक्षम करके इस जुड़ाव को और बढ़ाया जा सकता है। श्री पंडित ने अपनी राय साझा की कि विभिन्न देशों के पीआईओ के साथ-साथ भारत में उद्यमियों के बीच सहयोग, एक-दूसरे को बाजार पहुंच प्रदान करने, विशेषज्ञता, अनुभवों, पूंजी और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के मामले में लाभप्रद हो सकता है। इस सहयोग में बल गुणकों के रूप में कार्य करने और प्रवासी भारतीयों के योगदान की गति और पैमाने को बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंध को प्रगाढ़ करने की क्षमता है।

श्री अटेम गारंग देंग देकुएक, सदस्य, संक्रमणकालीन राष्ट्रीय विधान सभा, दक्षिण सूडान ने राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद से भेंट की, 11 जनवरी 2023

श्री अटेम गारंग देंग देकुएक, सदस्य, संक्रमणकालीन राष्ट्रीय विधान सभा, दक्षिण सूडान ने 11 जनवरी 2023 को राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद से भेंट की और दक्षिण सूडान में थिंक टैंक के साथ संभावित संस्थागत संबंध और अनुसंधान सहयोग पर चर्चा की। वह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के तहत भारत में थे।

राजदूत विजय ठाकुर सिंह, अध्यक्ष, टास्क फोर्स 7-टी20, भारत और भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक, ने थिंक 20 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस, 13 जनवरी 2023 को स्पॉटलाइट भाषण दिया, 13 जनवरी 2023

राजदूत विजय ठाकुर सिंह, अध्यक्ष, टास्क फोर्स 7-टी20, भारत, और भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक, ने 13 जनवरी 2023 को थिंक 20 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस के पूर्ण प्रथम सत्र में "सुधारित बहुपक्षवाद: एक वैश्विक अनिवार्यता" पर स्पॉटलाइट भाषण दिया।

भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र की भागीदारी के अवसर पर, "बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत-मिस्र संबंध" पर भारतीय वैश्विक परिषद पैनल चर्चा, 16 जनवरी 2023

भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र की भागीदारी के अवसर पर, आईसीडब्ल्यूए ने 16 जनवरी 2023 को "वैश्विक व्यवस्था को बदलने में भारत-मिस्र संबंध" पर चर्चा आयोजित की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (सीपीवी और ओआईए) डॉ. औसाफ सईद ने मुख्य भाषण दिया। राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने स्वागत भाषण दिया। भारत में मिस्र के राजदूत, महामहिम वाएल मोहम्मद अवाद हमद ने विशेष टिप्पणी की। नवदीप सूरी, प्रतिष्ठित फेलो, ओआरएफ, और मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के पूर्व राजदूत; डॉ. अतुल अनेजा, संपादक, इंडिया नैरेटिव; और टीसीआई सनमार केमिकल्स के अध्यक्ष श्री पी. एस. जयरामन चर्चाकर्ता थे।

चर्चा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत और मिस्र प्राचीन और महान सभ्यताओं के अलावा वैश्विक दक्षिण के लिए बुलंद आवाज हैं। 2023 गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में यह यात्रा मिस्र के राष्ट्रपति बनने के बाद से राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की

तीसरी भारत यात्रा थी। विश्व राजनीति में तेजी से बदलते इस परिदृश्य में, भारत और मिस्र जैसे देशों के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत और मिस्र के वर्तमान संबंधों का जायजा लेने के लिए धारणाओं को साझा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की 2015 में तीसरे भारत-अफ्रीका मंच के लिए और 2016 में भारत यात्रा के साथ संबंधों को गति मिली, जो एक राजकीय यात्रा थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विशेष रूप से यूएनजीए 2015, ब्रिक्स 2017 आदि के दौरान बैठकें कीं। दोनों देशों के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने की भी अत्यधिक संभावना है। वर्षों से, राष्ट्रों के बीच एक मजबूत रक्षा साझेदारी विकसित हुई है। यह सहयोग संयुक्त अभ्यास और रक्षा प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण मॉड्यूल में सक्रिय भागीदारी के रूप में प्रकट हो रहा है। 2000-21 से, मिस्र के छात्र आईसीसीआर और भारत-अफ्रीका फोरम साझेदारी के तहत छात्रवृत्ति सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। भारत ने मिस्र के छात्रों को 83 छात्रवृत्तियां दी हैं। भारत, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मिस्र के राजनयिकों की मेजबानी करेगा; सितंबर 2023 के महीने के दौरान 33 मिस्र के राजनयिकों के लिए एक समर्पित पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना दर्शाता है कि भारत मिस्र के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है।

यह कहा गया था कि भारत हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण देश है, और हिंद महासागर की सुरक्षा लाल सागर की सुरक्षा से शुरू होती है। स्वेज नहर पर मिस्र के लिए स्वेज नहर की सुरक्षा लाल सागर की सुरक्षा से शुरू होती है, जो दोनों देशों को भू-रणनीतिक रूप से एक साथ जोड़ती है। हिंद महासागर, स्वेज नहर और लाल सागर एक निरंतरता है जो एक दूसरे से बहती है।

चर्चाकर्ताओं ने सॉफ्ट पावर के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे बॉलीवुड एक महान कनेक्टर रहा है, विशेषकर महिलाओं के बीच। जैसे-जैसे दोनों अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं, इस तरह के आर्थिक विकास का लाभ उठाने के लिए युवा उद्यमियों और पेशेवरों का समर्थन करने की आवश्यकता है। युवाओं के बीच संबंधों के निर्माण के लिए उन्नत इंटर्नशिप कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

भारत और मिस्र के पास इस नई विश्व व्यवस्था को आकार देने की क्षमता, बैंडविड्थ और इतिहास है। दोनों देशों को वर्तमान भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक क्षण का लाभ उठाने और द्विपक्षीय स्थान का विस्तार करने के लिए बेहद महत्वाकांक्षी होने की आवश्यकता है और फिर न केवल विकासशील देशों के साथ बल्कि संयुक्त राष्ट्र, जी 20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक एजेंडे को प्रभावित करने में भी नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए।

"भारतीय विदेश नीति के 75 वर्षों का समारोह" पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 17-18 जनवरी 2023

भारतीय वैश्विक परिषद ने 17-18 जनवरी 2023 को सप्रू हाउस, नई दिल्ली में "भारतीय विदेश नीति के 75 वर्षों का समारोह" नामक दो दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई थी और इसमें भारत और विदेशों के पूर्व राजनयिकों और रक्षा कर्मियों, प्रख्यात विद्वानों, सामरिक विचारकों की भागीदारी देखी गई। संगोष्ठी का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद से इसके प्रक्षेपवक्र के साथ-साथ वर्तमान और भविष्य की नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श के माध्यम से भारतीय विदेश नीति के 75 वर्षों को चिह्नित करना था।

उद्घाटन सत्र में भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने आजादी के बाद पिछले सात दशकों में भारतीय विदेश नीति और इसके विकास की व्यापक रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपने पारंपरिक मूल्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, पिछले 75 वर्षों में भारत की विदेश नीति ने राष्ट्रीय हितों की अच्छी तरह से सेवा करते हुए, कई चुनौतियों को पार किया है और वैश्विक प्रवचन में मौलिक योगदान दिया है। भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है जिसमें सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित होना जारी है। भारत राष्ट्रों के समूह के बीच अपनी भूमिका को भलाई के लिए एक शक्ति और तर्क की आवाज के रूप में पूरा करना जारी रखेगा। भारत विभिन्न बहुपक्षीय या बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखेगा और विकासशील दुनिया की आवाज बना रहेगा।

'दमन से स्वतंत्रता तक: एक स्वतंत्र विश्व दृश्य' शीर्षक वाले पहले सत्र की अध्यक्षता ब्रिटेन में पूर्व उच्चायुक्त राजदूत नलिन सूरी और चीन एवं पोलैंड में पूर्व राजदूत ने की। सत्र के वक्ता विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक डॉ.अरविंद गुप्ता; स्वर्ण सिंह, सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; डॉ. संजय बारू, सदस्य, शासी निकाय, भारतीय वैश्विक परिषद; और राजदूत विष्णु प्रकाश, कनाडा और दक्षिण कोरिया में पूर्व राजदूत थे। सत्र में उपनिवेशवाद की बेड़ियों से भारतीय विदेश नीति के उद्भव पर विचार-विमर्श किया गया ताकि एक युवा और विकासशील राष्ट्र के स्वतंत्र विश्व दृष्टिकोण की नींव रखी जा सके। इसमें एक सभ्यतागत राज्य की विदेश नीति को आकार देने पर चर्चा की गई जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में फिर से उभरी। वक्ताओं ने भारत की समकालीन विदेश नीति को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके इतिहास, लोकाचार, संस्कृति और सभ्यतागत पृष्ठभूमि का अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बात पर चर्चा की गई कि उपनिवेशवाद के खिलाफ अपने संघर्ष में भारत ने तीसरी दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका कैसे निभाई। यह इस बात पर भी केंद्रित है कि आज के भारत की कहानी एक आकांक्षी राष्ट्र की है जो अपने विकास और विकास को वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों से अलग नहीं मानता है।

"मानदंडों की स्थापना: भारतीय मार्ग" पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता एमपी-आईडीएसए के पूर्व कार्यकारी परिषद के पूर्व सदस्य प्रोफेसर एसडी मुनि और जेएनयू के प्रोफेसर एमेरिटस ने की। सत्र के वक्ताओं में लीबिया और जॉर्डन में भारत के पूर्व राजदूत राजदूत अनिल त्रिगुणायत; राजदूत मंजीव सिंह पुरी, नेपाल और ब्रुसेल्स के पूर्व राजदूत; और राजदूत अजय बिसारिया, कनाडा और पाकिस्तान में पूर्व उच्चायुक्त। सत्र में

इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वर्तमान विश्व व्यवस्था महामारी, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक असमानताओं और डिजिटल कमजोरियों जैसी परस्पर चुनौतियों का सामना कर रही है। विशेषज्ञों ने ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और आतंकवाद से मुकाबले जैसी चुनौतियों के समाधान का नेतृत्व करने या योगदान देने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जी 20 और एससीओ जैसे विभिन्न क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत की भूमिका की जांच की। सत्र में स्वीकार किया गया कि भारत एक बहुलवादी और समावेशी वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानक वास्तुकला की नींव पर आधारित है।

'न्यू इंडिया: फॉरेन पॉलिसी इन द प्रेजेंट डिकेड' शीर्षक वाले तीसरे सत्र की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी ने की। सत्र के वक्ता अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत राजदूत अमर सिन्हा थे; ऑस्ट्रेलिया में पूर्व उच्चायुक्त और मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत रह चुके राजदूत नवदीप सूरी; और श्री रुद्र चौधरी, निदेशक, कार्नेगी इंडिया। सत्र में विशेषज्ञों ने एक सतत विकास साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया जो सहयोग के मार्ग पर एक नए संवाद को आकार दे रहा है। विश्वास, सम्मान, संप्रभुता, पारदर्शिता, सहयोग और साझेदार देश की आवश्यकताओं पर आधारित भारत के विकास साझेदारी मॉडल का सकारात्मक मूल्यांकन किया गया। भारत की विकास साझेदारी पैमाने और दायरे में बढ़ रही है और यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी है जो अपने दृष्टिकोण में मानव-केंद्रित है। यह स्वीकार किया गया कि भारत के पास एक स्वाद के साथ एक ऐसी राजनीति है जो विशिष्ट रूप से उसकी अपनी है जो इसके विस्तारित वैश्विक संबंधों, नए निर्माणों में इसकी भागीदारी और इसकी वैश्विक पहलों को आकार दे रही है।

"भारतीय विदेश नीति: विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य" पर चौथे सत्र की अध्यक्षता सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी के दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान के निदेशक डॉ सी राजा मोहन ने की। इस सत्र में वक्ता डॉ जी योन जंग, रिसर्च प्रोफेसर, हांकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, सियोल; निकोलस ब्लारेल, राजनीति विज्ञान संस्थान, लीडेन विश्वविद्यालय, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एसोसिएट प्रोफेसर; डॉ. अमृता नार्लीकर, अध्यक्ष, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआईजीए), जर्मनी; माइकल कुगेलमैन विल्सन सेंटर, वाशिंगटन, डीसी से। सत्र में इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि भारत की विदेश नीति को अन्य देशों/क्षेत्रों द्वारा कैसे देखा और देखा जाता है। विशेषज्ञों ने रेखांकित किया कि वैश्विक राजनीति में भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के साथ भारत के साथ सहयोग महत्वपूर्ण और अद्वितीय बना हुआ है। जबकि वर्तमान दुनिया संघर्ष और संघर्षों का सामना कर रही है, एक उभरती हुई शक्ति और प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत सभी देशों और वैश्विक अभिनेताओं के साथ समान रूप से गतिशील और रचनात्मक संबंधों के निर्माण में आश्वस्त है। इस बात पर चर्चा की गई कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्र भारत की वृद्धि और विकास, विदेश नीति के संचालन को कैसे देखते हैं और कैसे भारत एक नई विश्व व्यवस्था के उद्भव में एक सकारात्मक शक्ति है।

'इंडिया एंड द ग्लोबल ऑर्डर: सेटिंग द नैरेटिव' विषय पर सेमिनार के पांचवें सत्र की अध्यक्षता भारत के पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रूस के पूर्व राजदूत और बांग्लादेश में पूर्व उच्चायुक्त राजदूत पंकज सरन ने की। सत्र में वक्ताओं में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, चांसलर, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय; लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे (सेवानिवृत्त), सलाहकार, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार; और डॉ जोरावर दौलत सिंह, सहायक फेलो, चीनी अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली। इस सत्र में वक्ताओं ने चर्चा की कि भारत किस तरह से वैश्विक पहलों पर प्रतिक्रिया देने की भारत की विदेश नीति की बदलती प्रकृति को प्रतिबिंबित करके वैश्विक सामरिक आख्यान तैयार कर रहा है। दृष्टिकोण में यह सामरिक बदलाव इस बात से परिलक्षित होता है कि भारत, एक समुद्री और महाद्वीपीय शक्ति दोनों के रूप में, अपने पड़ोस और विस्तारित पड़ोस से परे एक वैश्विक नायक के रूप में अपनी भूमिका को कैसे आकार दे रहा है। सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत के आर्थिक प्रदर्शन, इसके विकास में आत्मविश्वास, आंतरिक राजनीतिक स्थिरता और लचीलापन जैसे विभिन्न कारकों ने भारत को

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में खुद को मजबूत करने की अनुमति दी है। भारतीय विदेश नीति को हाल के वर्षों में जटिल और अशांत दुनिया को नेविगेट करने और भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक लाभों का लाभ उठाने की क्षमता को सफलतापूर्वक दिखाने के लिए स्वीकार किया गया था।

"भारतीय विदेश नीति - अगले सात दशक" विषय पर अंतिम सत्र की अध्यक्षता स्पेन और रूसी संघ के पूर्व राजदूत राजदूत डी बी वेंकटेश वर्मा ने की थी। इस सत्र में वक्ताओं में प्रोफेसर अजय दर्शन बेहरा, अकादमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; चिंतामणि महापात्रा, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हिंद-प्रशांत स्टडीज के संस्थापक और मानद अध्यक्ष; और डॉ जोरावर दौलत सिंह, सहायक फेलो, चीनी अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली थे। वक्ताओं ने रेखांकित किया कि भारत की विदेश नीति घरेलू विकास, सुरक्षा और समृद्धि और घरेलू आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक साधन होने के अलावा, वैश्विक विकास और क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सकारात्मक योगदान दे रही है। यह आकलन किया गया था कि वर्तमान भू-राजनीतिक उथल-पुथल भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अवसर प्रदान कर सकती है। सत्र में उन क्षेत्रों पर जोर दिया गया जिनमें भारत को 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं का निर्माण करना होगा। विशेषज्ञों ने कहा कि दुनिया भर के देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की भारत की अनूठी क्षमता को देखते हुए एक बहु-ध्रुवीय दुनिया भारत की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल है।

इंडोनेशिया के राष्ट्रीय विकास योजना मंत्रालय के राजनीतिक, कानूनी, रक्षा और सुरक्षा मामलों के उप मंत्री स्लामेट सोएडारसोनो ने भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की, 18 जनवरी 2023

इंडोनेशिया के राष्ट्रीय विकास योजना मंत्रालय के राजनीतिक, कानूनी, रक्षा और सुरक्षा मामलों के उप मंत्री स्लैमेट सोएडारसोनो ने भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंधों और पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 जनवरी 2023 को भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की।

"भारत-बांग्लादेश संबंधों पर विचार" पर गोलमेज चर्चा, 19 जनवरी 2023

श्री सैयद बदरुल अहसन, वयोवृद्ध बांग्लादेशी संपादक के साथ "भारत-बांग्लादेश संबंधों पर विचार" पर भारतीय वैश्विक परिषद गोलमेज चर्चा 19 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता और संचालन श्री शांतनु मुखर्जी, सलाहकार, नटस्ट्राट और मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किया। राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जेएनयू, नई दिल्ली, और श्री दीपांजन रॉय चौधरी, राजनयिक मामलों के संपादक, द इकोनॉमिक टाइम्स, चर्चाकर्ता थे।

"संयुक्त राष्ट्र में एकजुटता, संपोषणीयता और विज्ञान के माध्यम से समाधान" पर 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष महामहिम श्री कसाबा कोरोसी द्वारा 40वां सप्रू हाउस व्याख्यान, 30 जनवरी 2023

77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष महामहिम श्री साबा कोरोसी ने 30 जनवरी 2023 को भारतीय वैश्विक परिषद में "संयुक्त राष्ट्र में एकजुटता, स्थिरता और विज्ञान के माध्यम से समाधान" पर 40वां सप्रू हाउस व्याख्यान दिया। भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने सत्र की अध्यक्षता की और कहा कि महामहिम कोरोसी को जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77 वें सत्र के

अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और वह सदस्य राज्यों के समुदाय की सेवा कर रहे हैं और 77 वें जीए सत्र के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में कई हितधारकों के साथ काम कर रहे हैं। कई मायनों में, उन्हें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का वास्तुकार कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका आज बहु-आयामी संकटों का सामना करने वाली दुनिया में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने और सभी सदस्य देशों की शांति और विकास की साझा खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत वैश्विक चुनौतियों के व्यापक और न्यायसंगत समाधान प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों के साथ एकजुटता की भावना के साथ काम करता है, चाहे वह शांति निर्माण और शांति स्थापना, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन या बहुपक्षवाद में सुधार हो। भारत के जी-20 की अध्यक्षता का विषय "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" एकता और एकजुटता के महत्व को दर्शाता है। विकास के प्रति भारत के दृष्टिकोण के मूल में संपोषणीयता है। भारत ने 2021 में मिशन LiFE, अर्थात लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया, जो प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका विकास के लिए मौलिक है। भारत ने एक प्रभावशाली डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना की है जिसका उपयोग स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए किया गया है।

77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (संयुक्त राष्ट्र आम सभा) के अध्यक्ष महामहिम श्री कसाबा कोरोसी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की दुनिया में, थिंक टैंक "सीखने, विश्लेषण और चर्चा के स्थान" हैं और चूंकि वे स्वतंत्र हैं, इसलिए वे भविष्य के लिए अभिनव समाधान प्रदान कर सकते हैं। वास्तव में, आज के संकटों की तात्कालिकता को देखते हुए, दायरे के बाहर देखने, सोचने और कार्य करने की आवश्यकता है। हमें आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। राष्ट्रपति एकजुटता (राष्ट्रों और लोगों के बीच), संपोषणीयता (यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे समाधान समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं) और विज्ञान (आम समझ की कमी को दूर करने के लिए) के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा दुनिया की संसद है और साथ में राष्ट्रों को दो-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से चुनौतियों का सामना करना है-वास्तविक परिणाम प्राप्त करने और मात्रा पर उत्पादन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र आम सभा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर भारत के समान सिद्धांतों को साझा करता है और यूक्रेन संकट सहित मुद्दों को हल करने के लिए कूटनीति और चर्चा के लिए भारत के आह्वान का समर्थन करता है। 2023 एजेंडा 2030 के लिए अधूरा बिंदु है, जो पिछड़ रहा है। सितंबर 2023 में एसडीजी शिखर सम्मेलन में, हमें काम के यथार्थ मूल्यांकन की आवश्यकता है। स्थानीय, उप-राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से एजेंडा 2030 लक्ष्यों को लागू करने का भारत का प्रयास सराहनीय है। यहां तक कि कोविड महामारी के दौरान भी, जो एसडीजी के लिए एक झटका था, भारत का योगदान, जैसे कि टीकों का निर्यात, और जी 20 की अध्यक्षता के माध्यम से

रिकवरी को बढ़ावा देना सराहनीय है। हमें संपोषणीयता परिवर्तन को मापने के लिए एक पद्धति की आवश्यकता है जो मानव कल्याण, प्राकृतिक पूंजी और हमारे निवेश के अन्य सभी पहलुओं को एकीकृत करती है। यह 'बियॉन्ड जीडीपी' पहल है। हम जो माप नहीं सकते उसे बदल नहीं सकते। सतत परिवर्तन पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिसके लिए पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता होगी। हमें अपनी नदियों, झीलों और महासागरों के भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हमें विज्ञान के माध्यम से सतत विकास के लिए अपने कार्यों को आधार बनाने की आवश्यकता है और इसमें 'नमामि गंगे' जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी नदियों को साफ करने और पुनर्जीवित करने के भारत के प्रयास सराहनीय हैं। बहुपक्षीय संस्थाएं कल के विचारों से आज की

चुनौतियों से पार नहीं पा सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की प्रक्रिया की आवश्यकता है जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा के एक तिहाई सदस्यों की मांग है। भारत ने सुधारों पर जोर दिया है और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी लाया है। पिछले सात दशकों से संयुक्त राष्ट्र में साझेदार के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति दी है, पोलियो जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद की है, महिलाओं को सशक्त बनाया है और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सैनिकों के माध्यम से मानवीय योगदान दिया है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, "वह परिवर्तन बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं"।

कारागुलोव बातिर-मुखम्मद अज़मातोविच, प्रमुख विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, किर्गिज़ गणराज्य, भारत के तीसरे एससीओ निवासी शोधकर्ता, 01 फरवरी 2023

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) (2022-2023) की भारत की अध्यक्षता के वर्ष में, भारतीय वैश्विक परिषद दिसंबर 2022 से जून 2023 तक विदेश मंत्रालय के सहयोग से एससीओ निवासी शोधकर्ता कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। सात महीनों में, प्रत्येक एससीओ सदस्य देश से एक नामांकित युवा शोधकर्ता (रूसी वर्णमाला क्रम के एससीओ अभ्यास का पालन करते हुए: कजाकिस्तान-दिसंबर 2022, चीन-जनवरी 2023, किर्गिस्तान-फरवरी 2023, पाकिस्तान-मार्च 2023, रूस-अप्रैल 2023, ताजिकिस्तान-मई 2023 और उजबेकिस्तान-जून 2023) एक महीने की अवधि के लिए भारतीय वैश्विक परिषद के साथ रहेंगे। कार्यक्रम में एससीओ विद्वान की बेंगलुरु, चेन्नई और पांडिचेरी की यात्रा का एक सप्ताह का मॉड्यूल शामिल है, जिसे भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा अपने समझौता-ज्ञापन साझेदार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस), बैंगलोर के सहयोग से समन्वित किया जा रहा है।

फरवरी 2023 के महीने में, भारतीय वैश्विक परिषद ने किर्गिज़ गणराज्य के एक एससीओ विद्वान कारागुलोव बातिर-मुखम्मद अज़मतोविच की मेजबानी की, जो भारतीय वैश्विक परिषद के एससीओ रेजिडेंट रिसर्चर्स प्रोग्राम के लिए भारत में तृतीय निवासी विद्वान हैं। वह डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक प्रमुख विशेषज्ञ और कोनराड एडेनॉयर फाउंडेशन और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी), जर्मनी के फेलो हैं। उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत सहित भारत के प्रमुख थिंक टैंक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ वार्ता की; मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए), नई दिल्ली; और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली।

उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत सहित भारत के प्रमुख थिंक टैंक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ चर्चा की; मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए), नई दिल्ली; और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली।

भारतीय वैश्विक परिषद-आरआईएसी वार्ता "भारत-रूस सामरिक साझेदारी: बदलती विश्व व्यवस्था में नई चुनौतियां और अवसर", 02 फरवरी 2023

भारतीय वैश्विक परिषद (भारतीय वैश्विक परिषद) ने रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद (आरआईएसी) के सहयोग से 2 फरवरी 2023 को सप्रू हाउस में "भारत-रूस सामरिक साझेदारी: बदलती विश्व व्यवस्था में नई चुनौतियां और अवसर" पर एक संवाद का आयोजन किया। उद्घाटन भाषण भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने दिया। आंद्रे कोर्तुनोव, महानिदेशक, आरआईएसी; महामहिम पवन कपूर, रूसी संघ में भारत के राजदूत; और महामहिम डेनिस अलीपोव, रूसी संघ के राजदूत का भारत में आगमन। यह वार्ता भारत और रूस के लिए चल रहे वैश्विक भू-राजनीतिक प्रवाह की पृष्ठभूमि में नए अवसरों और चुनौतियों पर केंद्रित थी।

उद्घाटन सत्र में, प्रतिभागियों ने दोहराया कि वर्षों से, दोनों देशों ने स्वतंत्र विदेश नीतियों को बनाए रखा है और वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्यों में बदलावों से निपटने के दौरान सामरिक स्वायत्तता का अनुसरण किया है। यह नोट किया गया कि कोविड-19 और यूक्रेन संकट से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, दोनों देशों ने अभिसरण और विचलन के मामलों पर नियमित वार्ता बनाए रखी। यह भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों की लचीली प्रकृति को दर्शाता है।

वार्ता का पहला सत्र "भारत और रूस में सुरक्षा एजेंडा" पर केंद्रित था। पैनल की अध्यक्षता आरआईएसी के कार्यक्रम निदेशक डॉ.इवान टिमोफीव ने की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) के अध्यक्ष और रूस के पूर्व राजदूत पी.एस. राघवन, आंद्रे कोर्तुनोव, आरआईएसी की महानिदेशक; दिमित्री ट्रेनिन, अग्रणी अध्येता, प्राइमाकोव नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस (आईएमईएमओ); और कैप्टन सरबजीत एस परमार, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन में सीनियर फेलो ने टिप्पणी की। प्रतिभागियों ने अनिश्चित सुरक्षा परिदृश्य और कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संकट के कारण उत्पन्न व्यवधानों के दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को भी स्वीकार किया और इसे उभरती विश्व व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक विकास के रूप में माना। सत्र में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के समावेशी दृष्टिकोण और एक नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया।

दूसरे सत्र में 'आर्थिक सहयोग: पारंपरिक और नवोन्मेषी क्षेत्र' विषय पर चर्चा हुई। सत्र की अध्यक्षता भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के यूरेशिया के पूर्व संयुक्त सचिव श्री अजय बिसारिया ने की। यह टिप्पणी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बेंगलुरु के डीन और प्रोफेसर प्रोफेसर डी सुबाचंद्रन, इवान टिमोफीव, कार्यक्रम निदेशक, आरआईएसी; श्री अमित भंडारी, सीनियर फेलो, ऊर्जा, निवेश और कनेक्टिविटी-गेटवे हाउस, मुंबई; डॉ लिडिया कुलिक, इंडिया स्टडीज की प्रमुख, स्कोलकोवो इंस्टीट्यूट फॉर इमर्जिंग मार्केट्स; डॉ चैतन्य गिरि, एसोसिएट प्रोफेसर, पर्यावरण और अंतरिक्ष अध्ययन, फ्लेम विश्वविद्यालय, पुणे; और डॉ एलेक्सी कुप्रियानोव, प्रमुख, हिंद महासागर क्षेत्र

केंद्र, आईएमईएमओ आरएएस ने की। यह ऊर्जा जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों पर केंद्रित था; नई प्रौद्योगिकियों, नवाचारों और डिजिटल अर्थव्यवस्था की भूमिका; दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और आपसी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अवसरों का वादा किया और प्रतिबंधों के कारण सहयोग की चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया। वक्ताओं ने पारस्परिक लाभ के लिए आर्कटिक और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया।

तृतीय सत्र में "उच्च शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग-भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक आधार" विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। वक्ताओं ने रूसी और भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच द्विपक्षीय शैक्षिक कार्यक्रमों और छात्रों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के महत्व को दोहराया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिनका पूरी क्षमता से दोहन किया जाना बाकी है। इस संबंध में सूचना साझा करने, युवा कार्यक्रमों और शिक्षा मेलों पर जोर देने की आवश्यकता है। समापन भाषण भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह और आरआईएसी की महानिदेशक डॉ. आंद्रे कोर्तुनोव ने दिया।

स्लोवाक गणराज्य के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के राजनीतिक मामलों के महानिदेशक श्री माइकल पावुक के साथ गोलमेज चर्चा, 09 फरवरी 2023

भारतीय वैश्विक परिषद ने 09 फरवरी 2023 को सप्रू हाउस में श्री माइकल पावुक, राजनीतिक मामलों की महानिदेशक, स्लोवाक गणराज्य के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के साथ एक गोलमेज चर्चा की मेजबानी की। इसकी अध्यक्षता राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक, भारतीय वैश्विक परिषद ने की। डॉ. शालिनी चावला, प्रतिष्ठित फेलो, सेंटर फॉर एयरपॉवर स्टडीज (सीएपीएस) (पाकिस्तान/अफगानिस्तान); डॉ. संजीव कुमार, सीनियर अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद (चीन); और प्रोफेसर भास्वती सरकार, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू (यूरोप), वक्ता थे। परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।

टिम हॉल, प्रथम सचिव (नीति), ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग, भारत ने भारतीय वैश्विक परिषद का दौरा किया, 10 फरवरी 2023

टिम हॉल, प्रथम सचिव (नीति), ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग, भारत ने भारतीय वैश्विक परिषद का दौरा किया और 10 फरवरी 2023 को डॉ. श्रीपति नारायणन, डॉ. प्रज्ञा पांडे और डॉ. समता मल्लेम्पति, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद के साथ वार्ता की। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

तिलक देवशेर द्वारा "पश्तून: एक विवादित इतिहास" पर पुस्तक चर्चा, 13 फरवरी 2023

भारतीय वैश्विक परिषद ने 13 फरवरी 2023 को सप्रू हाउस में तिलक देवशेर, सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा "द पश्तून्स: ए कंटेस्टेड हिस्ट्री" पर एक पुस्तक चर्चा का आयोजन किया। राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद ने चर्चा की अध्यक्षता की। राजदूत विवेक काटजू, अफगानिस्तान में पूर्व भारतीय राजदूत, और डॉ. शालिनी चावला, प्रतिष्ठित फेलो, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज चर्चाकर्ता थे।

अध्यक्ष ने अपनी परिचयात्मक टिप्पणी में तीन ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डाला, जिनका पश्तूनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहला 1747 में, जब अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान की स्थापना की, जिससे इसे एक राष्ट्र की भावना मिली। दूसरा, 1948 के बाद से अफगान राज्य की स्थापना के बाद, पश्तून और अफगान सिखों से लड़ रहे हैं। तीसरा 1893 में है, जब ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान के अमीर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रिटिश अपने साम्राज्य और सोवियत साम्राज्य के बीच एक बफर राज्य चाहते थे, लेकिन अफगानों के लिए इसका मतलब उनकी मातृभूमि का विभाजन था। पश्तूनों ने इस विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया है, न ही डूरंड रेखा को, और पश्तूनिस्तान मुद्दे को उठाया है।

लेखक ने उल्लेख किया कि पुस्तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में नहीं है, बल्कि इन देशों में रहने वाले पश्तूनों के बारे में है। पुस्तक इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करती है: वे कहां से आए थे? उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? अंग्रेजों के साथ संपर्क, डूरंड लाइन, खान अब्दुल गफ्फार खान और विभाजन की राजनीति, क्रांति और रूसी आक्रमण, 2001 में अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए मुजाहिदीन और गृह युद्ध, बीस वर्ष तक तालिबान विद्रोह और 2021 के बाद से उनके पुनरुत्थान, आईएसकेपी और अल कायदा के इनक्यूबेशन और इन घटनाओं में पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका के बारे में बात की।

पहले चर्चाकार राजदूत विवेक काटजू ने बताया कि पुस्तक को सात खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड बहुत ही जटिल विषयों को आसानी से सफलतापूर्वक नेविगेट करता है। उन्होंने तर्क दिया कि पश्तूनों पर हमारा बहुत सारा ज्ञान ब्रिटिश औपनिवेशिक साहित्य पर आधारित है, जो एक समस्या है क्योंकि इससे पश्तूनों का एक स्थिर विवरण हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में बताया गया है कि पाकिस्तान में पश्तून कैसे पनपे और हमें पश्तों को हिंसक लोगों के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि डूरंड दो कारणों से बदलने वाला नहीं है। एक है पाकिस्तान। दूसरा, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है, वह यह है कि अफगानिस्तान में गैर-पश्तून नहीं चाहते हैं कि डूरंड बदल जाए।

दूसरे चर्चाकर्ता डॉ. चावला ने कहा कि पुस्तक ने एक अस्पष्टीकृत विषय पर अद्वितीय ज्ञान प्रदान किया है और वर्तमान भू-राजनीतिक चुनौतियों की व्याख्या करने वाली गतिशीलता को सामने लाया है। पश्तूनों पर सूफीवाद और बरेलवी प्रथाओं के प्रभाव पर भी चर्चा होती है। उन्होंने डूरंड रेखा, पाकिस्तान में पश्तूनों के अधिकारों और प्रांतीय स्वायत्तता के लिए सीमांत गांधी की खोज, 1979 के सोवियत आक्रमण के बाद बदली भू-राजनीतिक गतिशीलता, तालिबान आंदोलन और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे को छुआ। उन्होंने तर्क दिया, पश्तून ध्रुवीकृत हैं और पाकिस्तान ने अपने सामरिक हितों को पूरा करने के लिए स्थिति में हेरफेर किया है।

भारत में सऊदी अरब साम्राज्य के राजदूत महामहिम सालेह ईद अल हुसैनी ने राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद से भेंट की, 16 फरवरी 2023

भारत में सऊदी अरब के राजदूत महामहिम सालेह ईद अल हुसैनी ने 16 फरवरी 2023 को भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक, राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की। भारत-सऊदी अरब संबंधों और परस्पर हित के मुद्दों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई।

भारत में ग्वाटेमाला गणराज्य के राजदूत, महामहिम श्री उमर कास्टानेडा सोलारेस ने भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की, 17 फरवरी 2023

भारत में ग्वाटेमाला गणराज्य के राजदूत महामहिम श्री उमर कास्टानेडा सोलारेस ने 17 फरवरी 2023 को राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद से भेंट की। भारत-ग्वाटेमाला संबंधों को और मजबूत करने और परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा हुई।

सीईएसआईसीएएम के निदेशक और कोलम्बिया के वाणिज्य मंत्री के सलाहकार डॉ. सोरया कारो वर्गास ने राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक से भेंट की, 20 जनवरी 2023

भारत में ग्वाटेमाला गणराज्य के राजदूत महामहिम श्री उमर कास्टानेडा सोलारेस ने 17 फरवरी 2023 को राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद से भेंट की। भारत-ग्वाटेमाला संबंधों को और मजबूत करने और परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा हुई।

लातविया गणराज्य के विदेश मंत्रालय की उप विदेश मंत्री सुश्री रीरे के साथ गोलमेज चर्चा, 01 मार्च 2023

भारतीय वैश्विक परिषद ने 01 मार्च 2023 को सप्रू हाउस में डॉ. गुंडा रीरे, संसदीय सचिव, विदेश मंत्रालय, लातविया गणराज्य के साथ एक गोलमेज चर्चा की मेजबानी की। राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रो उम्मू सलमा बावा, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू (यूरोप); प्रो. बी. आर. दीपक, प्रोफेसर, सीसी एंड एसईएएस, एसआईएस, जेएनयू (चीन); प्रो अजय दर्शन बेहरा, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अकादमी, जामिया मिलिया इस्लामिया (पाकिस्तान और अफगानिस्तान); और डॉ. प्रज्ञा पांडे, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद (हिंद-प्रशांत), वक्ता थे। परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।

उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए सूचना और विश्लेषणात्मक केंद्र (सीआईआरएस) के निदेशक राजदूत डोनियोर कुरबानोव नेभारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की, 03 मार्च 2023

उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध (सीआईआरएस) के लिए सूचना और विश्लेषणात्मक केंद्र के निदेशक राजदूत डोनियोर कुर्बानोव ने 03 मार्च 2023 को राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद से भेंट की। उनके साथ उज़्बेकिस्तान के राजदूत राजदूत दिलशोद अखातोव भी थे। भारत। परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। सीआईआरएस उज्बेकिस्तान में भारतीय वैश्विक परिषद का समझौता-ज्ञापन साझेदार है।

श्री डेमन विल्सन, अध्यक्ष और सीईओ, एनईडी, वाशिंगटन ने राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद से भेंट की, 06 मार्च 2023

श्री डेमन विल्सन, अध्यक्ष और सीईओ, एनईडी, वाशिंगटन ने 06 मार्च 2023 को राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद से भेंट की। हिंद-प्रशांत, परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और संस्थागत आदान-प्रदान पर चर्चा हुई।

श्री पैट्रिक कुगिल, वरिष्ठ विश्लेषक, द पोलिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (PISM), पोलैंड ने भारतीय वैश्विक परिषद का दौरा किया, 06 मार्च 2023

श्री पैट्रिक कुगिल, वरिष्ठ विश्लेषक, द पोलिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (पीआईएसएम), पोलैंड ने 06 मार्च 2023 को डॉ. निवेदिता रे, निदेशक अनुसंधान, भारतीय वैश्विक परिषद और डॉ. हिमानी पंत, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद के साथ वार्ता की। क्षेत्रीय, वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों और भारतीय वैश्विक परिषद और पीआईएसएम के बीच संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई।

प्रोफेसर चिसाको मासुओ, क्यूशू विश्वविद्यालय, जापान ने भारतीय वैश्विक परिषद का दौरा किया, 14 मार्च 2023

(एससीओ). प्रोफेसर चिसाको मासुओ, क्यूशू विश्वविद्यालय, जापान ने 14 मार्च 2023 को भारतीय वैश्विक परिषद का दौरा किया और डॉ. संजीव कुमार, डॉ. अतहर जफर, डॉ. पुनीत गौर, डॉ. तेशु सिंह और डॉ. टुनचिनमंग लंगेल सहित भारतीय वैश्विक परिषद के अनुसंधान संकाय के साथ वार्ता की। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) पर चर्चा हुई।

श्री अराई मासायोशी, महानिदेशक, मंत्री सचिवालय, अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जापान ने भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की, 14 मार्च 2023

14 मार्च 2023 को सप्रू हाउस में श्री अराई मासायोशी, महानिदेशक, सचिवालय, अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जापान ने भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक, राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की। परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।

डॉ. अलेक्सी ज़खारोव, अध्येता, हायर स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स (एचएसई), मास्को ने भारतीय वैश्विक परिषद रिसर्च फैकल्टी के साथ वार्ता की, 15 मार्च 2023

डॉ. अलेक्सी ज़खारोव, अध्येता, हायर स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स (एचएसई), मास्को ने 15 मार्च 2023 को सप्रू हाउस में भारतीय वैश्विक परिषद के शोध संकाय के साथ वार्ता की। "भारत और रूस के बीच एक नए व्यापार एवेन्यू के रूप में आईएनएसटीसी" पर चर्चा हुई।

जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री फुमियो किशिदा द्वारा 41वां सप्रू हाउस व्याख्यान, 20 मार्च 2023

जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा ने 20 मार्च, 2023 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में "हिंद-प्रशांत का भविष्य- 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' के लिए जापान की नई योजना-एक अपरिहार्य भागीदार के रूप में भारत के साथ मिलकर" विषय पर 41वां सप्रू हाउस व्याख्यान दिया। इस अवसर पर माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भी उपस्थित थे।

अपने व्याख्यान में, प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा ने कहा कि फ्री एंड ओपन हिंद-प्रशांत (एफओआईपी) जापान की विदेश नीति की आधारशिला है क्योंकि

यह टोक्यो की भारतीय वैश्विक परिषद सप्रू हाउस का एक मार्गदर्शक परिप्रेक्ष्य है। श्री अराई मासायोशी, महानिदेशक मंत्री सचिवालय, अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जापान ने 14 मार्च 2023 को वाणिज्य हाउस में भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह से भेंट की। परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय वैश्विक परिषद सप्रू हाउस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भागीदारी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया एक ऐसे चौराहे पर है जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रैंकों के भीतर और दरारें हो सकती हैं। पूर्वी यूरोप में विकास की प्रकृति के कारण, शांति और चुनौतियों की रक्षा करने की मौलिक चुनौती है जो "वैश्विक कॉमन्स" पर सामूहिक चिंताओं को कमजोर कर सकती हैं, जिसमें आज जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और साइबरस्पेस जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। और इस तरह ये नई चुनौतियां जापान की एफओआईपी नीति का हिस्सा हैं जो वैश्विक कॉमन्स की सभी चिंताओं को शामिल करती हैं। उन्होंने कहा कि यहां ध्यान देने योग्य प्रमुख कारकों में से एक यह तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक इतिहास-मोड़ पर है, जिसने विश्व व्यवस्था को आकार देने वाले भारत जैसे नए नायकों के साथ ग्लोबल साउथ का उदय देखा है। वैश्विक शक्ति संतुलन में इस बदलाव के कारण, वैश्विक शासन के बोझ को संबोधित करने के लिए राष्ट्रों के बीच अधिक समझ की आवश्यकता है। वैश्विक विमर्श में यह परिवर्तन भू-राजनीति को पार कर जाएगा क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होगा जो राष्ट्रों, समाजों और व्यक्तियों के विकास मॉडल को प्रभावित करेगा।

इस पृष्ठभूमि में, एफओआईपी को जापान द्वारा एक नीति अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच विभाजन और टकराव के प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों से विभिन्न विचारों को आत्मसात करना है। इसके लिए, एफओआईपी कनेक्टिविटी पर महत्वपूर्ण जोर देता है, जो स्वतंत्रता, कानून के शासन और एक वैश्विक मानक व्यवस्था पर प्रीमियम देगा जो महान समृद्धि को बढ़ावा देगा। कानून के शासन के संबंध में, एफओआईपी के बारे में टोक्यो की समझ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रमुख सिद्धांतों को बरकरार रखती है, जैसे कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और बल का उपयोग न करना। विविधता के इस मुद्दे के साथ-साथ समावेशिता और खुलापन भी समान रूप से जुड़ा हुआ

है। संक्षेप में, उन्होंने कहा, एफओआईपी सहयोग के चार स्तंभों पर आधारित है। ये हैं (i) शांति के लिए सिद्धांत और समृद्धि के लिए नियम, (ii) हिंद-प्रशांत मार्ग में चुनौतियों का समाधान, (iii) बहुस्तरीय कनेक्टिविटी और (iv) "समुद्र" के सुरक्षा और सुरक्षित उपयोग के प्रयासों को "हवा" तक विस्तारित करना।

भारतीय वैश्विक परिषद-विदेश मंत्रालय, एससीओ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: पुनःसंयोजन ~ पुनर्जीवन्तता, 23–24 मार्च 2023

भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से, भारतीय वैश्विक परिषद, सप्रू हाउस, नई दिल्ली ने 23-24 मार्च 2023 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन: पुनःसंयोजन ~ पुनर्जीवन्तता पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की भारत की अध्यक्षता मनाने के लिए आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया था और इसमें शिक्षाविदों, थिंक टैंक और एससीओ सदस्य, पर्यवेक्षक और संवाद सहयोगी देशों के साथ-साथ एससीओ सचिवालय के मिशन/राजनयिकों के प्रमुखों ने भाग लिया था। भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, कंबोडिया, कतर, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका (22 देशों) के प्रतिनिधियों ने एससीओ सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में पूर्ण और समापन सत्रों के अलावा, चार कार्यकारी-सत्र थे।

पूर्ण सत्र में भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य भाषण राजदूत दम्मू रवि, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया; एससीओ के उप महासचिव राजदूत ग्रिगोरी लोगविनोव ने विशेष संबोधन दिया। यह नोट किया गया कि एससीओ क्षेत्र के भीतर से व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ है और अपने सदस्यों के बीच आम सहमति से अपनी नीतियों को आगे बढ़ाता है। एससीओ के उद्देश्यों, जिसमें सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी को मजबूत करना शामिल है, की पुष्टि की गई। यह नोट किया गया कि दुनिया वैश्विक परिवर्तन के एक चरण में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें एक नई बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आकार ले रही है। चल रहे भू-राजनीतिक बदलावों को देखते हुए, एससीओ बेहतर समझ, अनुभवों और ज्ञान को साझा करने और बहुआयामी संवाद के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। भारत का यह मानना कि 'विश्व एक परिवार है' या वसुधैव कुटुम्बकम एससीओ की अध्यक्षता के प्रति उसके दृष्टिकोण की विशेषता है। भारत का प्रयास पर्यवेक्षकों और संवाद भागीदारों के साथ ठोस और अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ने का रहा है।

सम्मेलन के पहले कार्यकारी-सत्र "पुनर्संयोजन एंड लीड: एन्हांस्ड इंटीग्रेशन में एससीओ की भूमिका" की अध्यक्षता कजाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत राजदूत अशोक सज्जनहार ने की थी, और पैनल के सदस्य श्री ज़ुमाबेक साराबेकोव थे, जो एन नजरबायेव फाउंडेशन,

अस्ताना, कजाकिस्तान के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स के यूरेशियन स्टडीज प्रोग्राम के विशेषज्ञ और प्रमुख; डॉ. गोहर इस्कंदरियन, प्रमुख, ईरानी अध्ययन विभाग, ओरिएंटल स्टडीज संस्थान, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, आर्मेनिया; श्री लिम मेंघौर, निदेशक, मेकांग सेंटर, एशियन विजन इंस्टीट्यूट, नोम पेन्ह, कंबोडिया; अहमद कंडिल, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की इकाई के प्रमुख, और ऊर्जा अध्ययन कार्यक्रम के प्रमुख, अल-अहरम सेंटर फॉर पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, काहिरा, मिस्र; और श्री खिन माउंग जॉ, संयुक्त सचिव, म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, यंगून, म्यांमार थे। एससीओ सत्र में मुख्य रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक विकास की पृष्ठभूमि में एससीओ से संबंधित एकीकृत मुद्दों पर चर्चा की गई। एससीओ में मध्य एशिया की केंद्रीयता को रेखांकित किया गया। यह नोट किया गया कि क्षेत्र में शांति, संपोषणीयता एससीओ की सफलता के लिए एक शर्त है, हालांकि यूरेशियन देश तेजी से बदलती दुनिया में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आतंकवाद का संकट एससीओ के सभी देशों में शांति और संपोषणीयता को प्रभावित करता है और सामूहिक रूप से इस खतरे से पूरी ताकत से निपटने की आवश्यकता है। कट्टरवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर स्पेस का दुरुपयोग एससीओ के सामने आने वाली अन्य समस्याएं हैं।

सम्मेलन के दूसरे कार्य सत्र का शीर्षक "संपोषणीयता के लिए पुन: कनेक्शन: यूरेशिया के सुरक्षित पुन: उद्भव को सुनिश्चित करना" था और इसकी अध्यक्षता पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रूसी संघ में भारत के पूर्व राजदूत राजदूत पंकज सरन ने की थी। सत्र के पैनलिस्ट एससीओ अध्ययन के लिए चीन केंद्र के महासचिव श्री डेंग हाओ; एसआईआईएस के वरिष्ठ अध्येता, और एससीओ ब्लू बुक, चीन के कार्यकारी संपादक, (ऑनलाइन); सैदमुरोडोव ल्युटफिलो, निदेशक, तुलनात्मक आर्थिक अनुसंधान विभाग, अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी संस्थान, ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी; ओलेग एस मकारोव, निदेशक, बेलारूसी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक रिसर्च, मिन्स्क; बेलारूस, राजदूत जासिम इब्राहेम अल्नाजेम, भारत में कुवैत राज्य के राजदूत, नई दिल्ली; अलेक्जेंडर लुकिन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रमुख, राष्ट्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय, उच्च विद्यालय अर्थशास्त्र; निदेशक, पूर्वी एशियाई और एससीओ अध्ययन केंद्र, एमजीआईएमओ विश्वविद्यालय, रूस थे। एससीओ इस सत्र में कहा गया कि वैश्विक आर्थिक ध्यान पूर्व की ओर बढ़ रहा है, और भारत और चीन यूरेशिया में विकास के दो इंजन हैं। एससीओ के भीतर आर्थिक सहयोग को परियोजना कार्यान्वयन के माध्यम से मजबूत करने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान में अस्थिरता एससीओ देशों को कई तरह से प्रभावित करती है। क्षेत्र के देशों को अफगान लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को प्राप्त करने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय देशों को अफगान लोगों के लिए सहायता और मानवीय राहत प्रदान करने के प्रयास जारी रखने चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई और यह सुझाव दिया गया कि जलवायु कार्रवाई एससीओ के भीतर चर्चा का हिस्सा होनी चाहिए।

अंतिम सत्र "पुनर्संयोजन, सिंक्रनाइज़, ग्रो: क्वेस्ट फॉर एन्हांस्ड कनेक्टिविटी" की अध्यक्षता रूसी संघ में भारत के पूर्व राजदूत राजदूत डी.बी.वेंकटेश वर्मा ने की। सत्र में निम्नलिखित पैनल के सदस्य थे: श्री बातिर तुर्सनोव, उप निदेशक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल एशिया, ताशकंद, उजबेकिस्तान; श्री नगी अहमदोव, प्रमुख सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण केंद्र (एआईआर सेंटर), बाकू, अज़रबैजान; डॉ. सोडिकोव मेटारखोन, एसोसिएट प्रोफेसर, विश्व अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, ताजिकिस्तान के वित्त मंत्रालय के तहत ताजिक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स; सुश्री यासोजा गुणशेखरा, विदेश मंत्रालय, कोलंबो, श्रीलंका की अतिरिक्त सचिव/द्विपक्षीय मामले (पूर्व); डॉ. डी. सुबा चंद्रन, प्रोफेसर और डीन, स्कूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज; एनआईएएस, बैंगलोर, भारत; डॉ. एबेट्सम अल्टेनेइजी, सामुदायिक सेवा क्षेत्र के निदेशक, अमीरात सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च, संयुक्त अरब

अमीरात। कनेक्टिविटी के सभी पहलुओं के महत्व पर चर्चा की गई। एससीओ के भीतर बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के महत्व को दोहराया गया, यह देखते हुए कि कई एससीओ देश लैंडलॉक हैं। आईएनएसटीसी और चाबहार बंदरगाह के उपयोग जैसी कई पहलों के माध्यम से दक्षिण एशिया सहित विभिन्न क्षेत्रों के साथ मध्य एशियाई क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

सम्मेलन के चौथे और अंतिम कार्य सत्र का शीर्षक "लोगों को फिर से जोड़ना: दिलों और दिमागों को मजबूत करना" था। सत्र की अध्यक्षता पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त राजदूत अजय बिसारिया ने की और पैनल के वक्ता थे: श्री आसिफ खान, काउंसलर, भारत में पाकिस्तान उच्चायोग, नई दिल्ली; सुश्री अल्टीनाई कनातबेकोवना अलियास्करोवा, किर्गिज गणराज्य के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, बिश्केक, किर्गिस्तान; सुश्री सोयोलगेरेल न्यामजाव, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र के प्रमुख और वरिष्ठ अध्येता, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, मंगोलिया; डॉ अली शमीम, सहायक प्रोफेसर, मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी, माले, मालदीव; राजदूत अब्दुलरहमान अलगौद, बहरीन साम्राज्य के राजदूत, नई दिल्ली, बहरीन। इस बात पर जोर दिया गया कि एससीओ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और देश अपने साझा इतिहास, परंपराओं और संस्कृति के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह देखा गया कि एससीओ सदस्य देशों के बीच एक अंतर-सभ्यतागत संवाद की आवश्यकता है, और यह कि बौद्ध धर्म और सूफीवाद सहित ऐतिहासिक रूप से साझा अनुभवों का पुनरोद्धार एससीओ सदस्यों के बीच अधिक समझ पैदा कर सकता है। यह देखते हुए कि युवा भविष्य के नवाचार के वाहक हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिक युवा जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

भारतीय वैश्विक परिषद की महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह ने अपने समापन भाषण में रेखांकित किया कि एससीओ में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों पर सहयोग करने की इच्छा है। आतंकवाद, सीमा पार अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर खतरे और अफगानिस्तान की स्थिति एससीओ के सामने तत्काल चुनौतियों में से हैं। आर्थिक एकीकरण भविष्य के लिए एससीओ के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में रेल, सड़क, वायु, डिजिटल और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

भारतीय वैश्विक परिषद ने बेलारूसी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक रिसर्च, के साथ "अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग" पर समझौता-ज्ञापन का समापन किया, 23 मार्च 2023

भारतीय वैश्विक परिषद ने 23 मार्च 23 को बेलारूस के एक प्रमुख थिंक टैंक, बेलारूसी सामरिक अनुसंधान संस्थान (बीआईएसआर) के साथ "अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग" पर एक समझौता-ज्ञापन (MoU) संपन्न किया। राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद, और बीआईएसआर के निदेशक डॉ ओलेग एस मकारोव ने भारतीय वैश्विक परिषद और बीआईएसआर की ओर से समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

प्रोफेसर डी. सुबाचंद्रन ने एनआईएएस के अनुसंधान शोधकर्ता के साथ भारतीय वैश्विक परिषद शोध-संकाय के साथ वार्ता की, 27 मार्च 2023

27 मार्च 2023 को सप्रू हाउस में एनआईएएस के अनुसंधान विद्वानों के साथ प्रो. डी. सुबाचंद्रन ने भारतीय वैश्विक परिषद के शोध संकाय के साथ वार्ता की। उद्घाटन भाषण राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा दिया गया था। पाकिस्तान पर सत्र की अध्यक्षता जामिया के प्रो. अजय दर्शन बेहरा ने की और अफ्रीका पर सत्र की अध्यक्षता राजदूत राजीव भाटिया ने की। एनआईएएस भारतीय वैश्विक परिषद का समझौता-ज्ञापन साझेदार है।

आउटरीच कार्यक्रम

"भारत के स्वतंत्रता संग्राम और अमृत काल के दौरान वैश्विक भारत के उदय में भारतीय डायस्पोरा का योगदान" पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 10-11 जनवरी 2023

स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायस्पोरा इनिशिएटिव्स (ओडीआई) के सहयोग से 10-11 जनवरी 2023 को इंदौर में "भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय डायस्पोरा का योगदान और अमृत काल के दौरान वैश्विक भारत का उदय" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय वैश्विक परिषद और आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित की गई थी। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन थीं। उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि प्रो मार्कंडेय राय, वरिष्ठ सलाहकार, यूएन-हैबिटेट और संरक्षक, ओडीआई थे। भारतीय वैश्विक परिषद की सीनियर अध्येता डॉ. सुरभि सिंह ने परिषद की ओर से इसके प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

एनआईएएस क्षेत्र अध्ययन "द हराम्बी फैक्टर: भारत-अफ्रीका आर्थिक और विकास साझेदारी" पर भारत-अफ्रीका पुस्तक चर्चा, 30 जनवरी 2023

एनआईएएस ने 30 जनवरी 2023 को एनआईएएस, बैंगलोर में राजदूत गुरजीत सिंह की पुस्तक "द हराम्बी फैक्टर: इंडिया-अफ्रीका इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट साझेदारशिप" पर एक पुस्तक चर्चा का आयोजन किया। एनआईएएस के विद्वानों, शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों ने चर्चा में भाग लिया। एनआईएएस भारतीय वैश्विक परिषद का समझौता-ज्ञापन साझेदार है।

सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, एसआईएस, जेएनयू द्वारा आयोजित "द बाल्टिक्स इन ए चेंजिंग यूरोप" पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 23-24 फरवरी 2023

डॉ. हिमानी पंत, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद ने 23-24 फरवरी 2023 को सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, एसआईएस, जेएनयू द्वारा आयोजित "द बाल्टिक्स इन ए चेंजिंग यूरोप" पर 2-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने "यूक्रेन" पर एक पेपर प्रस्तुत किया। एंड बियॉन्ड: अंडरस्टैंडिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ़ बाल्टिक स्टेट्स"।

लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित "लैंड पोर्ट्स के माध्यम से व्यापार और कनेक्टिविटी: पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अवसर खोलना" पर पैनल चर्चा, 21 मार्च 2023

डॉ. टेमजेनमेरेन एओ, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एमएचए, जीओआई द्वारा लैंड पोर्ट डॉकी में आयोजित "ट्रेड एंड कनेक्टिविटी वाया लैंड पोर्ट्स: अनलीशिंग अपॉर्च्युनिटीज फॉर नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स" पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया। मेघालय, 21 मार्च 2023.

बोध गया ग्लोबल डायलॉग्स का 5वां संस्करण, 24-26 मार्च 2023

डॉ. तुंचिनमंग लंगेल, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद ने बोधगया, बिहार में 24-24-2019 को आयोजित बोधगया ग्लोबल डायलॉग्स के 5वें संस्करण में "भारत-जापान संबंध: अन्वेषण और बौद्ध धर्म कनेक्ट पर निर्माण" सत्र में एक वक्ता के रूप में भाग लिया। 26 मार्च 2023.

विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में "दक्षिण एशियाई भू-राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार" पर व्याख्यान, 28 मार्च 2023

डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी, अध्येता, भारतीय वैश्विक परिषद ने 28 मार्च 2023 को विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में "दक्षिण एशियाई भू-राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार" पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया।

भारतीय वैश्विक परिषद प्रकाशन

मुद्दा संक्षिप्त

1. डॉ. अरशद, तुर्किये-सीरिया तालमेल: आगे एक नया रास्ता? (13 जनवरी 2023)
2. डॉ. स्तुति बनर्जी, ब्राजील और राष्ट्रपति लूला के सामने चुनौतियां (13 जनवरी 2023)
3. डॉ. लक्ष्मी प्रिया, अमीरात चाँद पर पहुँचा (18 जनवरी 2023)
4. डॉ. श्रबाना बरुआ, 2022 से 2023 तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डांवाडोल नजर आती है (23 जनवरी 2023)
5. अंजलि सिंह, तुर्किये-इज़राइल संबंधों की बदलती गतिशीलता: क्षेत्रीय प्रभाव (24 जनवरी 2023)
6. डॉ. गौरी नारायण माथुर, डीआरसी में हालिया संकट: क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिक्रियाएं (24 जनवरी 2023)
7. डॉ. स्तुति बनर्जी, ब्राजील और जी20: वैश्विक दक्षिण की शक्ति (25 जनवरी 2023)
8. डॉ. नरेश बी. के., नेपाल में वर्तमान आर्थिक स्थिति (27 जनवरी 2023)

9. डॉ तुनचिनमांग लांगेल, कोरिया गणराज्य (आरओके) की "स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिए रणनीति" का पुनर्निर्माण बढ़ाया (31 जनवरी 2023)
10. मुस्कान, पूर्वी चीन सागर में जापानी सुरक्षा नीति (31 जनवरी 2023)
11. डॉ. प्रज्ञा पाण्डेय, ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंध: तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के प्रयास (01 फरवरी 2023)
12. डॉ. श्रीपथी नारायणन, क्या म्यांमार में फिर से लोकतंत्र लौट आएगा? (03 फरवरी 2023)
13. डॉ. टेमजेनमेरेन ए.ओ, इंडोनेशिया की जी20 अध्यक्षता: इसके एजेंडा को निर्धारित करने वाले कारक और प्राथमिकताएं (06 फरवरी 2023)
14. युवराज सिंह, किर्गिस्तान-ताजिकिस्तान संघर्ष: क्षेत्रीय सहयोग पर प्रभाव (07 फरवरी 2023)
15. डॉ. श्रीपति नारायणन, पंद्रहवें मलेशियाई आम चुनाव (07 फरवरी 2023)
16. डॉ. तेशु सिंह, पूर्वी चीन सागर विवाद: हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निहितार्थ (09 फरवरी 2023)
17. डॉ. गौरी नरेन माथुर, दक्षिण अफ्रीका और G20: प्राथमिकताएं और मुद्दे (20 फरवरी 2023)
18. राहुल अजनोटी, एससीओ में ईरान की सदस्यता: अपेक्षाएं बनाम वास्तविकता (21 फरवरी 2023)
19. डॉ तुंचिनमंग लंगेल, 2023 में सात के समूह (जी7) की जापान की अध्यक्षता से अपेक्षाएं (06 मार्च 2023)
20. डॉ. स्तुति बनर्जी, नई स्टार्ट संधि और हथियार नियंत्रण से पहले चुनौतियां (13 मार्च 2023)
21. पराग दास, उप-सहारा अफ्रीका में इज़राइल की बढ़ती गतिविधियां (24 मार्च 2023)

दृष्टिकोण

1. डॉ. सुरभि सिंह, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस और प्रवासी-बिजनेस कनेक्ट का लाभ उठाना (04 जनवरी 2023)
2. डॉ. गौरी नरेन माथुर, 2023-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मोजाम्बिक की गैर-स्थायी सदस्यता (06 जनवरी 2023)
3. डॉ. मोनिका गुप्ता, माल्टा और स्विट्जरलैंड का यूएनएससी का गैर-स्थायी सदस्य चुना जाना: एक आकलन (06 जनवरी 2023)
4. डॉ. टुनचिनमंग लांगेल, अमरीका-प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन और प्रशांत साझेदारी रणनीति: एक आकलन (06 जनवरी 2023)
5. डॉ स्तुति बनर्जी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए गैर-स्थायी सदस्य: इक्वाडोर के परिप्रेक्ष्य से (06 जनवरी 2023)
6. डॉ. गौरी नारायण माथुर, डीआरसी में हालिया संकट: क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिक्रियाएं (24 जनवरी 2023)
7. डॉ. टेम्जेनमेरेन एओ, फिलीपींस-अमेरिका सैन्य संबंधों में नया घटनाक्रम (08 फरवरी 2023)
8. डॉ. अथर जफर, दक्षिण काकेशिया स्थिर शांति की ओर बढ़ रहा है? (16 फरवरी 2023)
9. डॉ. हिमानी पंत, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्र की स्थिति का संबोधन:रूस की विदेश नीति की प्राथमिकताएं (28 फरवरी 2023)
10. डॉ. संजीव कुमार, रूस-यूक्रेन संघर्ष पर अपने रुख को संतुलित करने की चीन की कोशिश (06 मार्च 2023)
11. डॉ. अन्वेषा घोष, उच्च स्तरीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करने के लिए अफगान तालिबान से मुलाकात (09 मार्च 2023)

12. डॉ. श्रीपति नारायणन, क्या आसियान म्यांमार के प्रति अपना रुख़ सख़्त कर सकता है? (15 मार्च 2023)
13. डॉ. सुरभि सिंह, गतिशीलता के क्षितिज का विस्तार- भारत के नए युग के प्रवासन समझौते (15 मार्च 2023)
14. डॉ. तेशु सिंह, अमेरिका-चीन संबंध और चीनी जासूस गुब्बारे का विलक्षण मामला (15 मार्च 2023)
15. डॉ. लक्ष्मी प्रिया, सऊदी-ईरान समझौते का महत्व (16 मार्च 2023)
16. अवनि सबलोक, वैश्विक यूपीआई भुगतान प्रणाली की ओर बढ़ते कदम (16 मार्च 2023)
17. डॉ. प्रज्ञा पांडे, प्रधानमंत्री किशिदा ने 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' (एफओआईपी) को पुनर्जीवित किया (31 मार्च 2023)

आईसीडब्ल्यूए अतिथि कॉलम

1. मंगोलिया के मंत्री, "तर्कहीनता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध" त्सोग्तबातर दामदीन, संसद सदस्य और मंगोलिया के पूर्व विदेश मंत्री (17 जनवरी 2023)
2. एल्डोर टुलियाकोव, "वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन और उज़्बेक-भारत संबंधों की मुखरता" (20 जनवरी 2023)
3. संजय बारू, सांसद मुरलीधरन, एन. मनोहरन, असंगा अबेयगूनसेकरा, अथौल्ला ए. रशीद, अनूप मुद्गल, ए. सुब्रमण्यम राजू, प्रिया बहादूर, मालशिनी सेनारत्ने, जुवेंस एफ. रामासी और आर.एस. वासन, "भारत और भारतीय में द्वीप राज्य महासागर: उभरती भू-राजनीति और सुरक्षा परिप्रेक्ष्य" (01 फ़रवरी 2023)
4. राहुल कुलश्रेष्ठ और फ़ज़ूर रहमान सिद्दीकी, "बियॉन्ड फ़ेज़ एंड नज़र: व्यूज़ फ्रॉम इंडिया ऑन तुर्किये" (03 फ़रवरी 2023)
5. राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक उच्च नोट पर समापन: भारत की अवधि 2021-2022 का आकलन" (17 फ़रवरी 2023)
5. यूरी एम. यार्मोलिंस्की, विश्लेषक, बेलारूसी सामरिक अनुसंधान संस्थान, "शंघाई सहयोग संगठन के रास्ते पर बेलारूस: भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली में विश्लेषणात्मक केंद्रों के एससीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पूर्व संध्या पर विचार", 21 मार्च 2023

सप्रू हाउस शोधपत्र

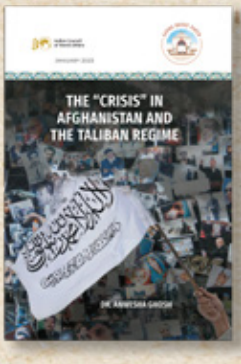

The "Crisis" in Afghanistan and the Taliban Regime

By Dr. Anwesha Ghosh,

(Indian Council of World Affairs 2023)

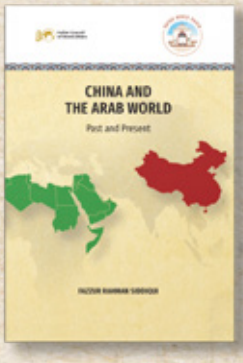

China and the Arab World: Past and Present

By Dr. Fazzur Rahman Siddiqui,

(Indian Council of World Affairs 2023)

An Assessment of the Prospective FTA between India and Australia

By Dr. Rahul Nath Choudhury,

(Indian Council of World Affairs 2023)

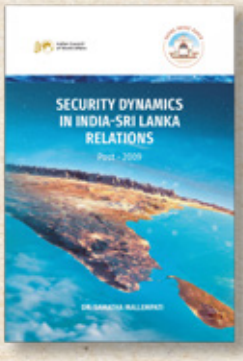

Security Dynamics in India-Sri Lanka Relations Post-2009

By Dr. Samatha Mallempati,

(Indian Council of World Affairs 2023)

China and the South Pacific: Unfolding Geopolitical Shifts in the Region

By Dr. Pragya Pandey,

(Indian Council of World Affairs 2023)

भारतीय वैश्विक परिषद पुस्तकें

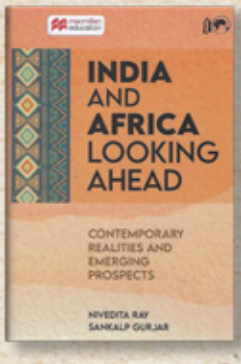

India and Africa Looking Ahead: Contemporary Realities & Emerging Prospects

Edited by Nivedita Ray and Sankalp Gurjar

(Indian Council of World Affairs, Macmillan Education, 2023)

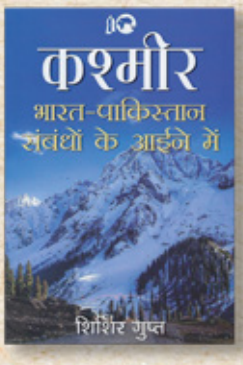

कश्मीर: भारत-पाकिस्तान संबंधों के आईने में

(Hindi Edition) शिशिर गुप्त

(भारतीय वैश्विक परिषद; प्रभात प्रकाशन, 2023)

G20@2023: The Roadmap to Indian Presidency

By V. Srinivas,

(Indian Council of World Affairs; Pentagon Press, 2023)

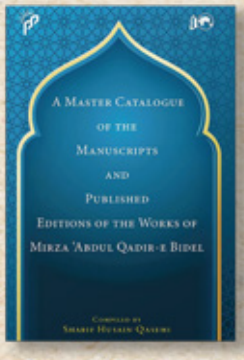

A Master Catalogue of the Manuscripts and Published Editions of the Works of Mirza 'Abdul Qadir-E Bidel

Compiled by Sharif Hussain Qasemi,

(Indian Council of World Affairs; Pentagon Press, 2023)

विशेष प्रकाशन

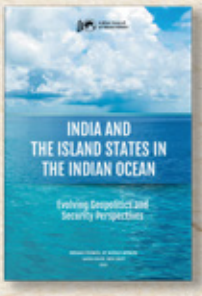

"India and the Island States in the Indian Ocean: Evolving Geopolitics and Security Perspectives"

By Sanjay Baru, M. P. Muralidharan, N. Manoharan, Asanga Abeyagoonasekera, Athaulla A. Rasheed, Anup Mudgal, A. Subramanyam Raju, Priya Bahadoor, Malshini Senaratne, Juvence F. Ramasy & R. S. Vasan,

(1 February 2023)

'बियॉन्ड फ़ेज़ एंड नज़र: व्यूज़ फ्रॉम इंडिया ऑन तुर्किये'

(Hindi Edition)

राहुल कुलश्रेष्ठ और फज्जुर रहमान सिद्दीकी

'कन्क्लुडिंग ऑन अ हाई नोट इन द UN सिक्यूरिटी कॉउंसिल: एन अस्सेस्मेंट ऑफ़ इंडिया'स टर्म 2021-2022

(Hindi Edition)

राजदुत टी.एस. तिरुमूर्ति

इण्डिया क्वार्टरली, ए जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स

विशेष अंक: भारत का बॉर्डरलैंड

खंड 79, अंक 1, मार्च 2023

संपादकीय

एक वैचारिक श्रेणी के रूप में 'बॉर्डरलैंड्स' को भूगोल, नृविज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, भाषाविज्ञान और भू-राजनीति से अनुशासनात्मक अंतर्दृष्टि द्वारा सूचित किया जाता है। इमैनुएल ब्रूनेट-जेली (2005) ने चार मुख्य विश्लेषणात्मक लेंस तैनात करने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए एक मॉडल का प्रस्ताव दिया जो सीमावर्ती राजनीति में संरचना और एजेंसी की जांच करते हैं। ये इस प्रकार हैं: (ए) बाजार की ताकतें और व्यापार प्रवाह, (बी) आसन्न सीमाओं पर बहु-स्केलर राज्य प्रक्रियाएं, (सी) सीमावर्ती समुदायों का राजनीतिक दबदबा और (डी) सीमावर्ती समुदायों की विशिष्ट संस्कृति। दक्षिण एशियाई सीमावर्ती क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए, हमें ब्रुनेट-जेली के सीमाओं के सिद्धांत को उपनिवेशवाद के बाद के चश्मे से फ़िल्टर करने की आवश्यकता है क्योंकि संप्रभुता, राष्ट्र-राज्य और इसके परिणामस्वरूप सीमाओं / सीमाओं का निर्धारण साम्राज्य के अनुभव में ऑन्कोलॉजिकल रूप से आधारित है। उदाहरण के लिए, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद, इतिहासकार और सार्वजनिक बौद्धिक युवाल नूह हरारी ने जोर देकर कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, "बाहरी आक्रमण द्वारा एक भी स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त देश को मानचित्र से मिटा नहीं दिया गया था" (हरारी, 2022)।

हरारी का बयान राष्ट्र, संप्रभुता और सीमाओं की महामारी श्रेणियों में एक गहरी ऐतिहासिक रूप से अंकित पदानुक्रम को दर्शाता है।

हरारी के दावे के विपरीत, चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण किया और हिमालयी क्षेत्र की सीमाओं को बदलते हुए इसे एशिया के राजनीतिक मानचित्र से मिटा दिया। क्या तिब्बत को 'वैश्विक' राजनयिक मान्यता प्राप्त थी, यह आईआर के यूरो-केंद्रित संस्थागतकरण का एक कार्य था जो वेस्टफेलियन मानदंडों को प्राथमिकता देता है। युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति के संस्थानों में तिब्बत की राजनयिक स्थिति निश्चित रूप से इस बात का निर्धारक नहीं थी कि तिब्बती राष्ट्र और इतिहास की भावना वाले लोग हैं जो अपनी भूमि और पहचान पर चीनी दावों का विरोध करना जारी रखते हैं। इसलिए, राष्ट्र, संप्रभुता और सीमाओं की गहरी अवधारणाओं को हटाना दक्षिण एशिया के उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रों के लिए समकालीन प्रासंगिकता की एक राजनीतिक परियोजना है और इस क्षेत्र की सीमावर्ती छात्रवृत्ति में सामने आना जारी है (देखें चटर्जी, 2018; पांडे, 2017)। इस छात्रवृत्ति के भीतर, दक्षिण एशियाई सीमावर्ती भूमि को न केवल साम्राज्य और उसके शक्ति पदानुक्रमों के बीच बल्कि उत्तर-औपनिवेशिक राज्य और इसकी कई परिधियों के बीच विवाद की साइट के रूप में कल्पना की जाती है (देखें कॉन्स एंड सान्याल, 2013; इब्राहिम और कोठियाल, 2022)। यहां, क्षेत्रीयता की शीर्ष-नीचे संप्रभु प्रक्रियाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिशीलता, प्रवाह और सामाजिक और सांस्कृतिक झुकाव के साथ वार्ता करती हैं। इसके परिणामस्वरूप अक्सर उत्तर-औपनिवेशिक राज्य अपने ऐतिहासिक और भौगोलिक मार्जिन के साथ एक खंडित राजनीतिक, प्रशासनिक और प्रभावी संबंध रखता है। कई सीमावर्ती विद्वान राष्ट्रीय और राजनीतिक इमैजिनरी के किनारे पर होने के कार्टोग्राफिक, राजनीतिक, भौतिक और भावनात्मक बोझ को आगे बढ़ाते हैं। रोलुआहपुइया (2022), जिइपाओ (2022), फिरदौश (2021), कोठियाल (2021), गेरगन (2020), इंडिया क्वार्टर्ली 79 (1) 7-10, 2023 © 2023 भारतीय वैश्विक परिषद (भारतीय वैश्विक परिषद), पुनर्मुद्रण और अनुमतियां: in.sagepub.com/journals-permissions-india, डीओआई: 10.1177/09749284221147275 journals.sagepub.com/home/iqq 8, इंडिया क्वार्टर्ली 79 (1) और इब्राहिम (2020) केंद्र और सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच सत्ता के पदानुक्रम पर ध्यान केंद्रित करें और उत्तर-औपनिवेशिक राज्य की मुक्ति क्षमता पर सवाल उठाएं क्योंकि यह अपनी सीमावर्ती भूमि पर अपनी राज्य बनाने की प्रक्रिया को लागू करता है।

जो राष्ट्र से संबंधित है और राज्य का एक वैध नागरिक है, वह तेजी से रक्त और मिट्टी की धारणाओं से जुड़ा हुआ है क्योंकि दक्षिण एशियाई राज्य अपनी कार्टोग्राफिक चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीयता और नागरिकता के प्रश्नों के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण लेते हैं। भारत की सीमाओं पर यह विशेष अंक अपनी हिमालयी सीमाओं और बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ भारत के सीमावर्ती समुदायों में राज्य के इस अनुभव पर प्रकाश डालता है। इस अंक के सभी शोध-पत्र इस क्षेत्र के युवा विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं जो जाति, क्षेत्र, नागरिकता, प्रवास और लिंग के आसपास केंद्रित अभिलेखीय या नृवंशविज्ञान हस्तक्षेप की पेशकश करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में राज्य-निर्माण पर लीमासेनला जमीर के पेपर ने दक्षिण एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य के किनारे पर एक सामरिक स्थान में अब तक उपेक्षित सीमा को बदलने में द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका को प्रकाश में लाया है। जमीर जे. पी. मिल्स, रॉबर्ट रीड, एंड्रयू क्लॉ और ओलाफ कैरो जैसे प्रभावशाली औपनिवेशिक प्रशासकों के विभिन्न पदों को एक साथ बुनने के लिए अभिलेखीय स्रोतों का उपयोग करते हैं, जो युद्ध के बाद क्राउन एजेंसी बनाने की वकालत करते हैं या इसके खिलाफ हैं, इस आशा के साथ कि ब्रिटेन भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी इस सामरिक सीमा पर नियंत्रण बनाए रखेगा। आज, यह ब्रिटिश साम्राज्य की एक अराजकतावादी, यहां तक कि एक विचित्र, अपेक्षा प्रतीत होती है। हालांकि, यह हमें हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के प्रति साम्राज्य के नस्लीय और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में एक स्पष्ट खिड़की प्रदान करता है, जो दुर्भाग्य से नौकरशाही मशीनरी में इतनी गहराई से शामिल था कि स्वतंत्रता पर पर्याप्त रूप से बदल नहीं सकता था।

स्वाति चावला ने खुलासा किया कि कैसे हिमालय में अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 'मंगोलियाई फ्रिंज' की नस्लीय कथा को सिक्किम दरबार ने सीमाओं और सीमाओं के औपनिवेशिक पुनर्गठन के बाद वार्ता में तैनात किया था। चावला ने यह स्थापित किया कि सिक्किमी अभिजात वर्ग ने स्वदेशीता के अनिवार्य आख्यानों को आगे बढ़ाया, जो लंबे समय से चली आ रही आर्थिक और धार्मिक प्रतिद्वंद्विता और हिमालयी समुदायों (भूटिया और लेप्चा) के बीच संघर्ष पर आधारित थे, ताकि नई दिल्ली के बजाय ल्हासा की ओर उन्मुख एक प्रेरक धार्मिक, राजनीतिक और जातीय पहचान बनाई जा सके। यह भारत में उभरने वाली औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर सिक्किम के लिए एक नई स्वतंत्र पहचान की खोज में किया गया था। चावला हमारा ध्यान राष्ट्रवादी सीमावर्ती प्रौद्योगिकियों की ओर आकर्षित करते हैं जो तब सामने आईं जब राजनीतिक उपनिवेशवाद के वादे के बाद छोटे हिमालयी राज्यों के बीच क्षेत्रीयकरण की स्वतंत्र मांगों का अनुकरण किया गया क्योंकि उन्होंने बड़े भारतीय गणराज्य के भीतर अपनी स्थिति पर विचार किया था। केतौखरीयू दो सीमा पार नागा जनजातियों की सीमा पार रहने की प्रथाओं को दर्शाता है, जिनकी स्वदेशी भूमि को भारत और

म्यांमार के बीच सीमाओं के औपनिवेशिक लागू होने के बाद से बनाया गया है। ये समूह नागरिकता की अस्पष्ट धारणाओं के माध्यम से भारत और म्यांमार के राज्यवादी विमर्शों पर वार्ता और विरोध कर रहे हैं। यह प्रतिरोध अक्सर जटिल होता है क्योंकि सीमाएं सत्ता संघर्ष के बहु-स्तरीय स्थल हैं और साथ ही साथ केंद्र और उसकी परिधि के बीच, सीमावर्ती समुदायों के भीतर विभिन्न गुटों के साथ-साथ सीमा पार शत्रुता और दृढ़ता के बीच विरोधी गतिशीलता पैदा करती हैं।

लेखक ने एक थोपी गई अंतरराष्ट्रीय सीमा के विघटनकारी प्रभाव के तहत रहने वाले कोन्याक और खियमनियुंगन नागाओं के एक ग्राउंडेड नृवंशविज्ञान अतिथि संपादकीय 9 अध्ययन के माध्यम से सीमा-निर्माण की थोपी गई शीर्ष-नीचे प्रकृति को कैप्चर किया है। थांगगोलेन किपगेन भारत-म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों से सिंगापुर तक कुकी प्रवास की सामाजिक गतिशीलता की जांच करता है। यह शोध-पत्र सिंगापुर में कुकी प्रवासियों के सामाजिक जीवन में चर्च की केंद्रीय भूमिका का पता लगाता है ताकि जातीय और रिश्तेदारी नेटवर्क के गठन को मैप किया जा सके जो एक वैश्विक शहर में इस प्रवासी को बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग बन गए हैं।

यह प्रवासी मुख्य रूप से घरेलू देखभाल के काम में लगी एकल महिलाओं और बेहतर आजीविका की तलाश में पलायन करने वाले पुरुषों का गठन करता है। किपगेन दर्शाता है कि सिंगापुर में कुकी प्रवासियों ने अपनी कुकी पहचान को कैसे फिर से हासिल किया, जिसे भारत और म्यांमार के औपनिवेशिक राज्यों के बीच क्षेत्रीय समूहों में विभाजित किया गया था। इसके विपरीत, भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों पर समीर शर्मा के शोध-पत्र में चर्चा की गई है कि गोरखाओं के सीमा पार समुदाय ने संबंधित मेजबान राज्यों के साथ औपनिवेशिक क्षेत्रीय समेकन के साथ अपने हितों को कैसे जोड़ा है। शर्मा का शोध-पत्र भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र में नागा और कुकी सीमा पार समुदायों के अनुभव के लिए एक उपयोगी काउंटरपॉइंट प्रदान करता है जो गोरखा समुदाय पर नागरिकता की क्षेत्रीय धारणाओं के टूटने वाले प्रभाव को दर्शाता है।

अनामिका रॉय ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों के जीवन पर नागरिकता की क्षेत्रीय धारणा के गहरे हाशिए के प्रभाव को उजागर किया है। रॉय नागरिकता को एक बहिष्करण अभ्यास के रूप में जांचने के लिए लैंगिक को एक लेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं जो इन बस्तियों में देश के राज्यविहीन टुकड़ों के रूप में मौजूद महिलाओं के पितृसत्तात्मक शोषण को बढ़ाता है। रॉय ने बताया कि कैसे महिलाएं राष्ट्र और इसकी पहचान के वाहक होने की भावात्मक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक लागतों को वहन करती हैं। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो महिलाएं नागरिक हैं, उन्हें राज्यहीन पुरुषों के लिए नागरिकता के मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है; या, यदि वे राज्यविहीन हैं, तो वे सामाजिक पदानुक्रम के निचले भाग में दूसरों के लिए कम मूल्य वाले वैवाहिक भागीदारों के रूप में काम करते हैं। किसी भी मामले में, वैवाहिक संबंधों के भीतर उनका सामाजिक मूल्य क्षेत्रीय भौतिकताओं से जुड़ा होता है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। अंत में, नोएल जोसेफ हिमालय सीमावर्ती भूमि पर मौजूदा साहित्य का सिंथेटिक पठन प्रदान करता है। जोसेफ साम्राज्य, जाति, क्षेत्र, युद्ध, नागरिकता, व्यापार, प्रवासन और पर्यावरण की चिंताओं में स्थित हिमालय पर छात्रवृत्ति को एक साथ लाता है ताकि इस क्षेत्र के दृष्टिकोण में एक औपनिवेशिक मोड़ के लिए जमीन तैयार की जा सके।

यह समीक्षा निबंध इस अंक में अन्य शोध-पत्रों की अंतर्निहित चिंताओं को रेखांकित करता है और दक्षिण एशियाई सीमावर्ती छात्रवृत्ति में भविष्य के शोध के लिए एक एजेंडा तैयार करने का प्रयास करता है। दक्षिण एशियाई सीमावर्ती क्षेत्र एक साथ उपनिवेशवाद के अपने सामान्य अनुभव से परिवर्तित सभ्यतागत और ऐतिहासिक आख्यानों के साथ-साथ (आईएम) गतिशीलता, प्रवाह, पहचान और अपनेपन की खंडित सरणी प्रस्तुत करते हैं। ये अतिव्यापी आख्यान भारत सहित दक्षिण एशियाई राज्यों की राज्य-निर्माण प्रक्रियाओं में गहराई से शामिल हैं। जबकि भारत अपने उपनिवेशवाद विरोधी इतिहास की ठोस क्षमता का उपयोग करने की आकांक्षा रखता है, इसकी सीमावर्ती भूमि से लोकतांत्रिक नागरिकता (होल्स्टन, 2009) का उदय हो रहा है। इस अंक के शोध-पत्र इस आकांक्षा को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न उठाते हैं।

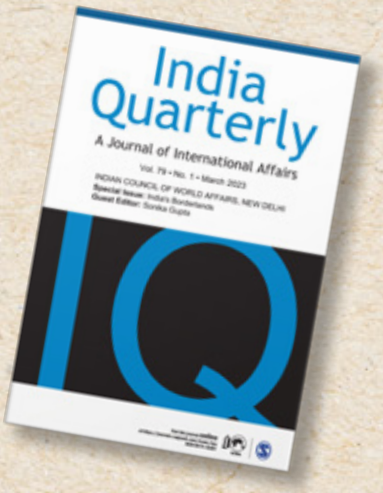

सोनिका गुप्ता
अतिथि संपादक, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास और तिब्बतस्केप्स

भारतीय वैश्विक परिषद के बारे में

भारतीय वैश्विक परिषद (ICWA) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद आज एक आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति शोध करती है। यह सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज परिचर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों की एक श्रृंखला नियमित रूप से आयोजित करती है और कई प्रकाशनों का प्रकाशन करती है। इसमें एक बहुत सी पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है, और यह 'इंडिया क्वार्टरली' पत्रिका प्रकाशित करती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए ने अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंकों और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं। परिषद की भारत में अग्रणी शोध संस्थानों, थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी है।

मेंटर : राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

संपादक : श्रीमती नूतन कपूर महावर, संयुक्त सचिव, आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

प्रबंध संपादक : डॉ. निवेदिता रे, निदेशक अनुसंधान, आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

सहायक संपादक : डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी, अनुसंधान अध्येता, आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

सहायक : सुश्री अन्विति मोहिले, सहायक प्रबंधक, MyGov/आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

हमसे जुड़ें

/Sapru.House @ICWA_NewDelhi /ICWA_NewDelhi www.icwa.in

/company/indian-council-of-world-affairs1

आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रक

वेबसाइट: https://www.icwa.in; दूरभाष नं 011-23317246 फैक्स नंबर 011-23310638